



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—ठप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

K9  
3/1997

सं 244]  
No. 244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 1997/ज्येष्ठ 29, 1919  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 1997/JYAISTHA 29, 1919

वित्त भंत्रालय

(आधिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1997

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1997

सा. का. नि. 328(य).—केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 53) की धारा 36 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 का ओर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1997 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(क) नियम 4 के उपनियम (3) में—

- (i) “चार सेटों” शब्दों के स्थान पर “दो सेटों” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “प्रत्यर्थी” शब्द जहां कही वह आता है, के स्थान पर “प्रतिष्ठादी” शब्द रखा जाएगा;
- (ख) नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

“5क. पुनर्विलोकन—(1) कोई ऐसा पक्षकार जो अभिलोक्य को देखने से ही प्रकट किसी गलती या अशुद्धि के आधार पर अधिकरण द्वारा किए गए आदेश से अपने को व्यक्तित्व समझता है और अपने विरुद्ध किए गए आदेश के पुनर्विलोकन की बांधा करता है तो वह ऐसा आदेश करने वाले अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा;

(2) पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ आवेदन को सत्यापित करते हुए शपथपत्र न लगा हो;

(3) जहां अधिकरण को यह प्रतीत हो कि पुनर्विलोकन के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा किन्तु जहां अधिकरण की यह राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए वहां वह उसे मंजूर करेगा;

परन्तु ऐसे किसी भी आवेदन को विरोधी पक्षकार को, उपस्थित होने और ऐसे आदेश के समर्थन में, जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है, सुनवाई के लिए पूर्व सूचना दिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा।

(ग) नियम 7 में, (i) उपनियम (1) में,—

(अ) "प्रत्येक आवेदन" शब्दों के स्थान पर "धारा 19 के अधीन प्रत्येक आवेदन, अन्तर्वर्ती आवेदन या अधिकरण, के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) "जहाँ अधिकरण अवस्थित है" शब्दों के स्थान पर "जो किसी अधिकरण की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर स्थित है" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (2) में की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात् :—

### सारणी

क्रम सं.	आवेदन की प्रकृति	संदेश फीस की रकम
1.	शोध्य ऋण की वसूली के लिए आवेदन—	
	(क) जहाँ शोध्य ऋण की रकम 10 लाख रुपए है	12,000 रुपए
	(ख) जहाँ शोध्य ऋण की रकम 10 लाख रुपए से अधिक है रुपए के शोध्य ऋण या उसके भाग के लिए एक हजार रुपए	12,000 रुपए जमा दस लाख रुपए से अधिक, प्रत्येक एक लाख किन्तु अधिकतम 1,50,000 रुपए के अधीन रहते हुए संदेश फीस का 50 प्रतिशत
2.	पुनर्विलोकन के लिए आवेदन	10 रुपए
3.	अन्तर्वर्ती आदेश के लिए आवेदन	5 रुपए <sup>1</sup> ;
4.	वकालतनामा	

(घ) नियम 9 और नियम 11 में "प्रत्यर्थी" शब्द जहाँ-जहाँ वह आता है, के स्थान पर "प्रतिवादी" शब्द रखा जाएगा;

(ङ) नियम 12 में,—

(i) उपनियम (1) में—

"प्रत्यर्थी" शब्द के स्थान पर जहाँ-जहाँ वह आता है, के स्थान पर "प्रतिवादी" शब्द रखा जाएगा।

(आ) "चार पूर्ण सेट" शब्दों के स्थान पर "दो पूर्ण सेट" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप नियम (2) में,—

(अ) "प्रत्यर्थी" शब्द के स्थान पर "प्रतिवादी" शब्द रखा जाएगा।

(आ) "आवेदन" शब्दों के स्थान पर "आवेदक" शब्द रखा जाएगा।

(iii) उप नियम (3) में "प्रत्यर्थी" शब्द के स्थान पर "प्रतिवादी" शब्द रखा जाएगा।

(vi) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :—

"(4) यदि प्रतिवादी उप नियम (1) के अधीन या आवेदन की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को उत्तर फाइल करने में असफल रहता है तो अधिकरण आवेदन पर जैसा उचित समझे, तुरन्त आदेश पारित कर सकेगा;

(5) जहाँ प्रतिवादी किसी भी विस्तीर्ण संस्था को शोध्य ऋण की रकम को पूर्णतया या भागतया स्वीकार करता है, वहाँ अधिकरण ऐसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत रकम तक का, ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर आवेदक को संदाय किए जाने का आदेश करेगा। ऐसा न करने पर अधिकरण अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत शोध्य ऋण की रकम तक का प्रभाग-पत्र जारी कर सकेगा;

(6) अधिकरण, किसी भी समय प्रयाप्त कारण से किसी विशिष्ट तथ्य या तथ्यों को शपथपत्र द्वारा प्रभागित किए जाने के लिए या किसी गवाह के शपथपत्र को ऐसी किसी शर्त पर जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे, सुनवाई के दौरान पढ़े जाने का आदेश कर सकेगा:

परन्तु अधिकरण को जहाँ यह प्रतीत होता है कि जहाँ आवेदक या प्रतिवादी गवाह को प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित किए जाने की वांछा करता है और ऐसा गवाह उपर्युक्त किया जा सकता है तो ऐसे गवाह के साक्ष्य को शपथपत्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने का आदेश नहीं किया जाएगा;

(7) यदि प्रतिवादी आवेदक द्वारा किए गए दावे के संदाय के अपने दायित्व से इंकार करता है तो अधिकरण आवेदक के शपथपत्र

पर जिसे मामले के तथ्यों की जानकारी है या जिसने अधिकारी के सत्यापन पर आवेदन की अन्तर्वस्तु और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की बाबत शपथपत्र दिया हैं, पर कार्रवाई कर सकेगा;

(8) “बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) की धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबंध, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक द्वारा फाइल की गई बैंककार बही में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति की लागू होगा।

(च) नियम 16 में, “प्रत्यार्थी” शब्द के स्थान पर “प्रतिवादी” शब्द रखा जाएगा।

(छ) नियम 17 के उपनियम (1) में “लंबित आवेदन” शब्दों के स्थान पर “प्रत्येक लंबित आवेदन” शब्द रखे जाएंगे।

(ज) नियम 23 के खण्ड (viii) में “प्रत्यार्थी” शब्द के स्थान पर “प्रतिवादी” शब्द रखा जाएगा।

3. उक्ता नियमों के प्ररूप में “प्रत्यार्थी” शब्द जहां कहीं भी वह आता है, के स्थान पर “प्रतिवादी” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 18(2)93-समन्वय]

डी. आर. एस. चौधरी,

संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम सा. का. नि. 564 (अ) तारीख 5 अगस्त, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 351(अ), तारीख 31 मार्च, 1994 द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1997

#### THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) AMENDMENT RULES, 1997

**G.S.R. 328 (E):**—In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (53 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993, namely:—

1. (1) short title and commencement.—These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure) rules 1993,

(hereinafter referred to as the said rules),

(a) in rule 4, in sub-rule (3),—

(i) for the words “four sets”, the words “two sets” shall be substituted;

(ii) for the word “respondent” wherever it occurs, the word “defendant” shall be substituted;

(b) after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

“5A. Review- (1) Any party considering itself aggrieved by an order made by the Tribunal on account of some mistake of error apparent on the face of the record desires to obtain a review of the order made against him, may apply for a review of the order to the Tribunal which had made the order.

(2) No application for review shall be made after the expiry of a period of sixty days from the date of the order and no such application shall be entertained unless it is accompanied by an affidavit verifying the application.

(3) Where it appears to the Tribunal that there is no sufficient ground for a review, it shall reject the application for review should be granted, it shall grant the same:

Provided that no such application shall be granted without previous notice to the opposite party to enable him to appear and to be heard in support of the order, a review of which is applied for”.

(c) in rule 7,—

(i) in sub-rule (1),

(A) for the words "Every application", the words and figures "Every application under Section 19, interlocutory application or application for review of decision of Tribunal" shall be substituted;

(B) For the words "where a Tribunal is located", the words "located at any place within local limits of the jurisdiction of a Tribunal", shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

**"TABLE**

Serial Number	Nature of application	Amount of Fee Payable
1.	Application for recovering of debts due,—	
	(a) Where amount of debt due is Rs. 10 lakhs	Rs. 12,000
	(b) Where amount of debt due is above Rs. 10 lakhs	Rs. 12,000 plus Rs. 1,000 for every one lakh of debt due or part thereof in excess of Rs. 10 lakhs, subject to a maximum of Rs. 1,50,000
2.	Application for review	50 per cent of the fee paid
3.	Application for interlocutory order	Rs. 10
4.	Vakalatnama	Rs. 5";

(d) in rules 9 and 11, for the word "respondent" wherever it occurs, the word "defendant" shall be substituted;

(e) in rule 12,—

(i) in sub-rule (1),—

(A) for the word "respondent" at both the places where it occurs, the word "defendant" shall be substituted;

(B) for the words "four complete sets" the words "two complete sets" should be substituted;

(ii) in sub-rule (2),—

(A) for the word "respondent" the word "defendant" shall be substituted;

(B) for the word "application" the word "applicant" should be substituted;

(iii) in sub-rule (3), for the word "respondent" the word "defendant" shall be substituted;

(iv) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:

(4) If the defendant fails to file the reply under sub-rule (1) or on the date fixed for hearing of the application, the Tribunal may proceed forthwith to pass an order on the application as it thinks fit.

(5) Where a defendant makes an admission of the full or part of the amount of debt due to a bank or financial institution, the Tribunal shall order such defendant to pay the amount, to the extent of the admission, by the applicant within a period of one month from the date of such order failing which the Tribunal may issue a certificate in accordance with section 19 of the Act to the extent of amount of debt due admitted by the defendant.

(6) The Tribunal may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts may be proved by affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing, on such conditions as the Tribunal thinks reasonable:  
Provided that where it appears to the Tribunal that either applicant or defendant desires the production of a witness for cross examination, and that such witness can be produced an order shall not be made authorising the evidence of such witness to be given by affidavit.

(7) If the defendant denies his liability to pay the claim made by the applicant, the Tribunal may act upon the affidavit of the applicant who is acquainted with the facts of the case or who has on verification of the record sworn the affidavit in respect of the contents of application and the documents as evidence.

(8) Provisions contained in section 4 of the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891) shall apply to a certified copy of an entry in a banker's book furnished along with the application filed under sub-section (1), of section 19 by the applicant".

(f) in rule 16, for the word "respondent" the word "defendant" shall be substituted;

(g) in rule 17, in sub-rule (1), for the words "Pending application", the words "each pending application" shall be substituted.

(h) in rule 23, in clause (viii), for the word "respondent" the word "defendant" shall be substituted.

3. In the Form to the said rules, for the word "respondent" wherever it occurs, the word "defendant" shall be substituted.

[F. No. 18 (2) 93-Coord.]

D. R. S. CHAUDHARY, Jt. Secy,

**Note:**—The principal rules were published vide GSR 564 (E) dated 5th August, 1993 and subsequently corrigendum was issued vide GSR 351 (E) dated 31st March, 1994.

1532-61/97-2

